हिन्दी पाक्षिक

महानगर स्तंभ

RNI NO. RAJHIN/2017/70561

पृष्ठ संख्या.... 3

❒ वर्ष-8 ❒ अंक-14 जयपुर, सोमवार 15 जुलाई, 2024 ❒ एक प्रति 5 रुपये ❒ कुल पृष्ठ-4

5 साल में 4 लाख भर्तियों की घोषणा

कर्मचारियों को सस्ता तो किसानों को ब्याज मुक्त लोन

जयपुर

राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने भजनलाल सरकार का पहला फुल बजट 10 जुलाई को पेश किया। प्रदेश में 21 साल बाद मुख्यमंत्री की जगह वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने लगभग दाई घण्टे तक बजट पेश किया। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि अब राजस्थान में पंचायत चुनाव एक साथ ही होंगे। उन्होंने 15 लाख महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना की भी घोषणा की। वहीं, रोडवेज में नई भर्तियों के साथ हेल्थ और पुलिस विभाग में 9 हजार से ज्यादा नए पदों का सृजन किया गया है। मेरिट में आने वाले स्कूली स्टूडेंट्स को अब फ्री टैबलेट और इंटरनेट भी दिया जाएगा। वहीं, सरकार अब काशी विश्वनाथ की तर्ज पर खाटूश्याम कॉरिडोर बनाएगी। इससे पहले वित्त मंत्री ने भाषण की शुरुआत में कहा कि पिछली सरकार में हुई पेपर लीक की घटना को हमारी सरकार ने रोका और माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा गिरफ्तारी की है। आगे भी ऐसे काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे 10 संकल्प हैं। इन्हीं को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं।

दीया कुमारी बोलीं- हमारे दस संकल्प हैं

1. प्रदेश को 350 बिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाना
2. पानी, बिजली, सड़का का विकास
3. सुनियोजित शहरी विकास
4. किसानों का सशक्तिकरण
5. औद्योगिक विकास
6. विरासत भी, विकास भी की सोच के साथ धरोहर संरक्षण
7. पर्यावरण संरक्षण
8. सबके लिए स्वास्थ्य और मानव संसाधन विकास
9. वंचित परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा
10. गुड गवर्नेंस, परफॉर्म, रीफॉर्म और ट्रांसफॉर्म

खेती-किसान: 5 लाख किसानों ब्याज मुक्त लोन

- ❒ राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन शुरू करने की घोषणा। सभी जिलों में पानी बचाने और सिंचाई के लिए 50 करोड़ खर्च होंगे।
- ❒ ईआरसीपी से जुड़ी घोषणाओं के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्ष का आरोप था कि जो घोषणाएं कांग्रेस सरकार ने की थी, उन्हें ही रिपीट किया है।

- ❒ नहरी क्षेत्र में डिग्गी निर्माण के लिए 5 हजार किसानों को अनुदान दिया जाएगा। 5 हजार करोड़ खर्च किए जाएंगे।
- ❒ 31 मार्च 2024 तक लंबित बिजली कनेक्शन की पेंडिंग को समाप्त करने के लिए एक लाख 45 हजार कनेक्शन देने की घोषणा की गई।
- ❒ किसानों को मॉडर्न कृषि उपकरण खरीदने के लिए अनुदान मिलेगा। मॉडर्न कस्टमर हायर सेंटर की संख्या बढ़ाई जाएगी।
- ❒ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में अलग से बोर्ड बनेगा। गोवर्धन परियोजना की शुरुआत होगी।
- ❒ लाख नए किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इस बार 3500 करोड़ के शॉर्ट टर्म लोन बांटे जाएंगे।
- ❒ दीर्घकालिक कृषि ऋण के लिए बजट दोगुना कर दिया। 50 करोड़ की जगह 100 करोड़ का बजट रखा गया।
- ❒ समय पर फसली कर्ज चुकाने वाले किसानों को 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा।

स्वास्थ्य: 4000 नर्सिंगकर्मियों के नए पद सृजित

- 27 हजार करोड़ का रुपए का प्रावधान स्वास्थ्य के लिए किया गया। यह पूरे बजट का 8.26 प्रतिशत है।
- आयुष्मान भारत योजना की तरह मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (मां) योजना शुरू होगी। आईपीडी के साथ डे केयर पैकेज जुड़ेगा। शिशुओं और छोटे बच्चों के इलाज के लिए नए पैकेज जोड़े जाएंगे।
- छोटे स्थानों पर निजी अस्पतालों के इंपैनलमेंट के नियमों में रियायत दी जाएगी।
- गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच के लिए मां योजना के तहत वाउचर दिया जाएगा।
- हर विधानसभा क्षेत्र में एक आयुष्मान मॉडल सीएचसी शुरू होगा। यहां मॉर्च्युरी बनाई जाएगी।
- अस्पतालों के लिए मां हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू होगा। इसके तहत 15 हजार करोड़ के काम करवाए जाएंगे।
- 1500 डॉक्टरों और 4000 नर्सिंगकर्मियों के नए पद सृजित होंगे।
- राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत होगी। प्रदेशवासियों का पीएचसी स्तर पर ई-हेल्थ रिकॉर्ड बनेगा।

पुलिस: 5500 नए पदों का सृजन

- पुलिस में 5500 नए पद सृजित करने की घोषणा।
- जयपुर, जोधपुर, कोटा के साथ 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में 1500 अतिरिक्त ट्रैफिक वॉलंटियर लगाए जाएंगे।
- पुलिस को 750 मोटरसाइकिल और 500 हल्के वाहन दिए जाएंगे।

सामाजिक सुरक्षा: मिलेगा सस्ता लोन

- गोविंद गुरु जनजाति विकास योजना शुरू करने की घोषणा, इस योजना के तहत आदिवासियों के विकास के काम होंगे। वन अधिकार के तहत पट्टे दिए जाएंगे।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को 25 हजार का अतिरिक्त अनुदान देने की घोषणा।
- पाक विस्थापितों को प्रति परिवार एक लाख रुपए की सहायता दी जाएगी।
- स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सीएम स्वनिधि योजना शुरू होगी।
- बाबासाहब अंबेडकर आदर्श ग्राम योजना की घोषणा।
- एसएसी-एसटी के कर्मचारियों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

शिक्षा: स्कूल स्टूडेंट को मुफ्त में टैबलेट और इंटरनेट

- राजस्थान सरकार ने विवि के कुलपतियों का नाम अब बदल दिया है। अब कुलपति को कुलगुरु कहा जाएगा।
- प्रदेश में भरतपुर, बीकानेर और अजमेर के इंजीनियर कॉलेज को राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पर 300 करोड़ खर्च होंगे।
- स्कूलों में 350 करोड़ की लागत से लाइब्रेरी और टॉयलेट सहित बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

महिला एवं बाल विकास: 15 लाख महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी

- हर विधानसभा में 5 नई आंगनबाड़ी खोली जाएगी।
- आदिवासी समुदाय के बच्चों के लिए 250 नई मां बाड़ी खोली जाएगी।
- आंगनबाड़ी के बच्चों को 3 दिन दूध दिया जाएगा। दूध पाउडर के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- जिला स्तर पर कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनेंगे। 35 करोड़ खर्च होंगे।
- बालिकाओं को पुलिस-सैनिक में भर्ती दिलाने के लिए संभागों में बालिका सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा।
- 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा।
- सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को 2.5 फीसदी सालाना ब्याज दर पर कर्ज देने की घोषणा।

संपादकीय

पीएम मोदी की मास्को यात्रा का कूटनीतिक महत्व

अपने तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय बैठक के लिए रूस को अपने पहले विदेशी दौरे के रूप में चुना। रूस पश्चिमी देशों से अलग-थलग पड़ रहा है, ऐसे में यह दौरा काफी महत्वपूर्ण है। इस यात्रा का स्पष्ट संदेश है कि रूस भारत की रणनीतिक गणना में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और भारत बाहरी दबावों के आगे नहीं झुकेगा। प्रधानमंत्री मोदी उसी दिन पुतिन से मिल हैं, जिस दिन नाटो वाशिंगटन डी.सी. में अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। यूक्रेन-युद्ध के बाद से ही रूस को पश्चिमी शक्तियों द्वारा अलग-थलग कर दिया गया है ढ अन्य देश भी रूस के साथ अपने संबंधों को लेकर सतर्क हो गए हैं। ग्लोबल साउथ में भारत के अलावा चीन ने रूस को वित्तीय मंदी और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव से बचाने में मदद की। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मार्च 2023 में दोबारा चुने जाने के बाद अपने पहले विदेशी दौरे के लिए रूस का चयन किया था। उधर पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत ने भी यूक्रेन- रूस युद्ध के दौरान आर्थिक संबंधों को कायम रखा। भारत ने रूस की आलोचना से इनकार करने के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र में उसके खिलाफ मतदान से भी परहेज किया। इसके अतिरिक्त, भारत ने रूस से तेल आयात पर पश्चिमी देशों की धमकियों को नजरअंदाज किया है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले वित्तीय वर्ष में रूस के साथ भारत का व्यापार 65 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो कि दो साल पहले तक अकल्पनीय था। हालांकि, मॉस्को के साथ भारत का वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन 2021 के बाद से आयोजित नहीं हुआ है। पिछले दो वर्षों में, भारत की पश्चिमी देशों के साथ बढ़ती नजदीकियों के कारण रुसी कूटनीतिज्ञों में चिंता बढ़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ चीन और रूस के बीच बढ़ती नजदीकियों को लेकर भारत आशंकित रहता है। रूस और चीन के बीच घनिष्ठ साझेदारी भारत के लिए चिंता का विषय है, खासकर तब जब भारत सीमा पर चीनी आक्रामकता का सामना कर रहा है।नई दिल्ली का प्रारंभिक अनुमान था कि युद्ध अल्पकालिक होगा और स्थितियाँ शीघ्र ही सामान्य हो जाएंगी। परंतु, युद्ध के जारी रहने के कारण, नई दिल्ली को अब गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। रूस और पश्चिमी देशों के बीच जारी खींचतान से भारत की कूटनीति गहन दबाव में है। न केवल भारत के प्रति पश्चिमी देशों की आलोचना तीव्र हुई है, बल्कि मुद्रास्फीति का बोझ भी बढ़ा है।

प्रदूषण एवं प्लास्टिक मुक्त राज्य के लिए संकल्पित राज्य सरकार

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पूरे राज्य को प्रदूषण मुक्त करने एवं सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से मुक्त करने के लिए राज्य भर में प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। एक ओर जहाँ वृहद स्तर पर विभिन्न विभागों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं निजी संस्थाओं के सहयोग से पौधरोपण का कार्य किया जा रहा है वही हर घर को प्लास्टिक केरी बैग्स से मुक्त करने के लिए मंडल के अधिकारियों द्वारा घर- घर जाकर न केवल सिंगल यूज प्लास्टिक के वस्तुएं उपयोग नहीं करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है बल्कि कपडे के थैले बाँटकर प्लास्टिक कैरी बैग्स का का उपयोग नहीं करने की भी शपथ दिलवाई जा रही है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव एन विजय ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रदूषण मुक्त राज्य की संकल्पना को साकार करने के क्रम में राज्य अग्रसर है और सिंगल यूज प्लास्टिक एवं प्लास्टिक कैरी बैग्स का उपयोग न के बराबर हो इसके लिए सार्थक प्रयास धरातल स्तर पर किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कार्यालय कार्यों, नियम-कायदे बनाने के साथ उन्हें समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना हमारी मौलिक जिम्मेदारी है जिसके तहत मंडल के अधिकारी एवं कर्मचारी घर- घर तक इस मुहीम को लेकर जा रहे है और कपड़े के थैलों का वितरण कर प्लास्टिक कैरी बैग्स उपयोग नहीं करने के लिए शपथ दिलवा रहे है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की प्रदूषण एवं प्लास्टिक मुक्त राज्य की व्यापक एवं दूरगामी सोच को साकार करने के हर स्तर पर हर संभव प्रयास किये जा रहे है।

प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में हो कपड़े का थैला

सदस्य सचिव ने कहा कि मंडल के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर कपड़े के थैले वितरित करने की इस मुहिम का एक ही उद्देश्य है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक के हाथ में प्लास्टिक कैरी बैग की जगह कपड़े का थैला दिखाई दे वही व्यापारिक संस्थानों एवं दुकानों पर भी कपड़े के थैले ही उपयोग में लिए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रयास किया जायेगा कि मंडल की यह मुहिम तब तक जारी रहे जब तक प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में कपड़े का थैला नहीं आ जाता। उन्होंने इस मुहिम में शामिल सभी सार्वजनिक, निजी संस्थानों का धन्यवाद देते हुए कहा कि सभी की भूमिका इस मुहिम का अहम भाग है। इस दौरान अधीक्षण वैज्ञानिक अधिकारी नेहा अग्रवाल के नेतृत्व में जगतपुरा स्थित रिद्धायशी सोसाइटी में कपड़े के थैलों का वितरण किया गया साथ ही प्लास्टिक कैरी बैग्स उपयोग नहीं करने, कचरे का समुचित प्रबंधन करने एवं पर्यावरण संरक्षण करने की शपथ दिलवाई गई. इस दौरान मौजूद सोसायटी के वरिष्ठ सदस्यों ने मंडल द्वारा चलायी जा रही मुहिम की सराहना करते हुए कहा कि अन्य लोगों तक मंडल के प्रदूषण मुक्त राज्य के सन्देश को प्राथमिकता से पहुंचना सुनिश्चित करेंगे।

राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, विधिक सहायता समिति की बैठक आयोजित

जयपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश), जयपुर महानगर द्वितीय के अध्यक्ष चन्द्र प्रकाश श्रीमाली की अध्यक्षता में 11 जुलाई को राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, विधिक सहायता के तहत अधिवक्तागण को देय मानदेय एवं अण्डर ट्रायल परीक्षण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पल्लवी शर्मा, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश), जयपुर महानगर द्वितीय ने बताया कि माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी एक्शन प्लान में दिए गए विभिन्न दिशा-निर्देशों की पालना में बैठक का आयोजन किया गया है।

बैठक में पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत कुल 32 प्रार्थना-पत्र रखे गए जिन पर कमेटी के अध्यक्ष व सदस्यगण द्वारा विचार-विमर्श पर प्रतिकर राशि/अवार्ड पारित किए गए। मीटिंग के दौरान पीड़ित प्रतिकर में कुल 14 लाख 25 हजार रूपए की राशि का अवार्ड पारित हुआ। इसी के साथ विधिक सहायता के तहत नियुक्त अधिवक्तागण के देय मानदेय के संबंध में भी आवश्यक कार्यवाही की जाकर अधिवक्तागण को नियमानुसार देय मानदेय के ऑर्डर जारी किए गए। साथ ही अंडर ट्रायल बंदी जो विभिन्न कैटेगरी में कारागार में निरुद्ध है उनकी रिहाई की अनुशंसा कर संबंधित न्यायालयों को भेजे जाने के निर्देश एवं आदेश प्रदान किए। बैठक में अनीष दाधीच, न्यायाधीश श्रम न्यायालय क्रम सं.01, जयपुर महानगर द्वितीय, शिव कुमार, न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण क्रम सं. 1, जयपुर महानगर द्वितीय, मांडवी राजवी, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर द्वितीय, राशि डोगरा डूडी, पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर उत्तर, अमित कुमार, पुलिस उपायुक्त, जयपुर शहर पश्चिम, पवन शर्मा, अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, संत कुमार जैन, लोक अभियोजक, राकेश मोहन, अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर उपस्थित रहे।

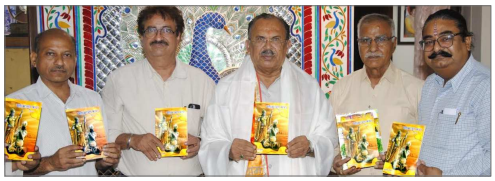

विधान सभा अध्यक्ष देवनानी ने पुस्तक व स्मारिका का किया विमोचन

जयपुर। राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भरतपुर के 291 वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में प्रकाशित स्मारिका का 8 जुलाई को यहां विधान सभा में विमोचन किया। देवनानी ने ब्रजभाषा के वरिष्ठ साहित्यकार गोपाल लाल गुप्ता द्वारा लिखित पुस्तक महाभारत भाग दो का भी विमोचन किया। देवनानी ने स्मारिका और पुस्तक प्रकाशन के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। भरतपुर जिला शासन - प्रशासन, मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री की थीम पर आधारित स्मारिका में केंद्र एवं राज्य में मंत्री रहे जनप्रतिनिधिगण सहित उच्च न्यायालय, सेना, पुलिस, प्रशासन, वन एवं विदेश सेवा में उच्च पदों पर रहे भरतपुर जिले के मूल निवासियों का संक्षिप्त परिचय संकलित किया गया है। ऐतिहासिक खानवा युद्ध के प्रतिशोध में बीकानेर का राती घाटी युद्ध, श्री राम मंदिर एवं बंसी पहाड़पुर के पत्थर संपदा का अंनूठा इतिहास, डॉक्टर रांगेय राघव के साहित्य सृजन, ईआरसीपी परियोजना इत्यादि आलेखों का भी स्मारिका में समावेश किया गया है। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार गुलाब बत्रा, महासचिव डॉ. प्रदीप चतुर्वेदी, कोषाध्यक्ष गोपाल गुप्ता, संपादन मण्डल के सदस्य, विनोद गेरा, राजेंद्र राज, जगदीश गुप्ता, हरेन्द्र चीमा और अजय नागर उपस्थित थे। स्मारिका के मुख्य पृष्ठ पर लोहागढ़ दुर्ग एवं सुजान गंगा नहर तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का चित्र है। स्मारिका में मुख्यमंत्री पद और भरतपुर के संदर्भ में जगन्नाथ पहाड़िया एवं भजनलाल शर्मा के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को रेखांकित किया गया है। आरंभ में परिषद के पदाधिकारीयो ने पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र से विधान सभा अध्यक्ष देवनानी का स्वागत किया। ब्रजभाषा में गोपाल गुप्ता की पुस्तक महाभारत भाग दो का विमोचन - राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने ब्रजभाषा के वरिष्ठ साहित्यकार गोपाल गुप्ता की ब्रजभाषा में लिखित पुस्तक महाभारत भाग द्वितीय का भी विमोचन किया। जयपुर पल्स प्रकाशन द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में महाभारत को मात्र 90 पृष्ठों में विवेचित किया गया है। पुस्तक में गीता का सार भी बताया गया है।

प्रदेश के 4 करोड़ 35 लाख व्यक्तियों को दिया जा रहा है खाद्य सुरक्षा का लाभ

जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने 12 जुलाई को विधानसभा में कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश की 4 करोड़ 46 लाख की सीलिंग के विरुद्ध करीब 4 करोड़ 35 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने के लिए प्राप्त आवेदनों के आधार पर शेष रिक्त स्थानों पर शीघ्र ही पात्र व्यक्तियों को जोड़ा जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि 23 हजार 172 सहरिया जनजाति के लाभार्थियों एवं 1 लाख 66 हजार सामाजिक सुरक्षाधारी विशेष योग्यजन को मिलाकर लगभग 2 लाख लाभार्थियों का नाम खाद्य सुरक्षा में जोड़ने का काम प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त जनाधार कार्ड से केवाईसी के बाद 1.5 लाख नाम और जोड़े जाएंगे जिनमें विशेषयोग्यजन भी शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि इस समय खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने के लिए 13 लाख 90 हजार आवेदन लम्बित हैं, जिनमें से अधिकतम सीमा को ध्यान में रखते हुए लगभग 7 लाख को शीघ्र ही योजना में जोड़ने का काम किया जाएगा। इससे पहले विधायक मनीष यादव के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खाद्य मंत्री ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत चयनित पात्र लाभार्थियों को जनवरी, 2023 से दिसम्बर 2028 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नि शुल्क खाधान्न उपलब्ध कराया जा रहा है/कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि नवीन सरकार के गठन के पश्चात् खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किये जाने हेतु नवीन आवेदन प्राप्त नहीं करके पूर्व में प्राप्त कुल 19.58 लाख आवेदन में से लंबित आवेदन लगभग 13.9 लाख में से परीक्षण पश्चात नाम जोडने की कार्यवाही विभागीय स्तर पर प्रक्रियाधीन है। गोदारा ने बताया कि वर्तमान में वर्ष 2024-25 में संकल्प पत्र में पृथक से लक्ष्य निर्धारित नहीं है।

राज्यपाल ने मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को शपथ दिलाई

जयपुर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 9 जुलाई को राजभवन में मोहन लाल लाठर को मुख्य सूचना आयुक्त तथा सुरेश चंद गुप्ता, महेंद्र कुमार पारख और टीकाराम शर्मा को राज्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलाई। इन सभी ने ईश्वर के नाम पर हिन्दी भाषा में शपथ ली। आरंभ में राज्यपाल मिश्र को मुख्य सचिव सुधांश पंत ने मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तो को शपथ दिलाने के लिए आग्रह किया। राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने लाठर को मुख्य सूचना आयुक्त तथा सुरेश चंद गुप्ता, महेंद्र कुमार पारख और टीकाराम शर्मा को राज्य सूचना आयुक्त बनने पर बधाई दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, राज्य मंत्री मण्डल के सदस्यगण, भारतीय प्रशासनिक एवं पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारीगण, राज्यपाल सचिव कविता सिंह, प्रमुख विशेषाधिकारी गोविन्द राम जायसवाल सहित अनेक गणमान्यजन मौजूद थे।

विश्व जनसंख्या दिवस पर राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या देश-दुनिया के लिए चिंता का विषय है। बढ़ती आबादी के कारण जल, जमीन और अन्य संसाधनों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि ये संसाधन प्रकृति में सीमित हैं। उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि से भी विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होती हैं। परिवार नियोजन हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, जिससे भावी पीढ़ी संसाधनों का उचित मात्रा में उपयोग कर सके। शर्मा ने कहा कि प्रदेश में सुदृढ़ चिकित्सा तंत्र एवं बेहतर परिवार कल्याण सेवाओं के कारण राजस्थान मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित संकेतकों में देश के अन्य राज्यों से बेहतर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना देखा है, उसे पूरा करने के लिए संसाधनों पर जनसंख्या के दबाव को कम करना जरूरी है। राज्य सरकार इस संकल्प को पूरा करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। यह एक ऐसा संकल्प है, जो सबकी सहभागिता से ही मूर्त रूप लेगा।

मुख्यमंत्री 11 जुलाई को जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्व जनसंख्या दिवस का उद्देश्य परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों के महत्व पर लोगों की जागरूकता बढ़ाना है। बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रकृति का संतुलन निरन्तर बिगड़ता जा रहा है, जलवायु परिवर्तन इसी का हिस्सा है। बढ़ती जनसंख्या आर्थिक विकास, रोजगार,

आय वितरण, गरीबी और सामाजिक सुरक्षा को भी प्रभावित करती है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, स्वच्छता, पानी, भोजन एवं ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयासों पर भी इसका व्यापक असर पड़ता है।

परिवार नियोजन से जनसंख्या वृद्धि में स्थिरता होगी सुनिश्चित

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए परिवार नियोजन एक प्रभावी कदम है। साथ ही, समाज में जागरूकता बढ़ाकर जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि की दर निरन्तर कम हो रही है। सतत् विकास लक्ष्य 2030 के अनुसार कुल प्रजनन दर (टीएफआर) का लक्ष्य 2.1 है, जबकि राज्य की कुल प्रजनन दर 2.0 है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में कार्मिकों की संवेदना और सेवा का बहुत महत्व होता है। मरीज के लिए चिकित्सक परमात्मा स्वरूप होता है। चिकित्सा अभियान, टीकाकरण की सफलता इस विभाग के कार्मिकों की कड़ी मेहनत से ही सुनिश्चित होती है। उन्होंने कहा कि गांव-ढाणी तक बेहतर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना हमारी प्राथमिकता है। प्रदेश में आभा आईडी के माध्यम से मरीज अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल तरीके से स्टोर कर सकते हैं। इसके जरिये रोगी एवं चिकित्सक को रोग एवं इलाज की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध हो सकेगी।

परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार का हुआ वितरण

मुख्यमंत्री ने परिवार कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार वितरित किए। राज्य में उत्कृष्ट कार्यों के लिए बांसवाड़ा को प्रथम स्थान, ब्यावर को द्वितीय, केकड़ी को तृतीय, भीलवाड़ा को चतुर्थ एवं शाहपुरा को पांचवा स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान किए गए। इसी तरह पीपीआईयूसीडी निवेशन में ब्यावर को प्रथम, सलूम्बर को द्वितीय तथा चित्तौड़गढ़ को तृतीय स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कृत किया गया। साथ ही, निजी अस्पताल एवं महाविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, राजकीय चिकित्सा संस्थान एवं महाविद्यालय, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत तथा व्यक्तिगत श्रेणी में भी पुरस्कार दिए गए। समारोह में मुख्यमंत्री शर्मा ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की आयुष्मान राजस्थान ई-मैग्जीन का अनावरण एवं विश्व जनसंख्या दिवस पर पोस्टर का विमोचन भी किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, निदेशक आरसीएच डॉ. सुनित सिंह राणावत सहित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, चिकित्सक, नर्सिंगकर्मी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

विश्व जनसंख्या दिवस 2024

नई दिल्ली। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने 11 जुलाई को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल की उपस्थिति में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ वर्चुअली बैठक का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का विषय था ÷मां और बच्चे की भलाई के लिए गर्भधारण का स्वस्थ समय और अंतराल÷। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत में विश्व जनसंख्या का 1ध्5 हिस्सा रहता है। उन्होंने जनसंख्या को स्थिर रखने की दिशा में काम करने की पुनः पुष्टि और पुनः प्रतिबद्धता के रूप में विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है, जब भारत के परिवारों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, जिसे केवल छोटे परिवारों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करने की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि महिलाएं परिवार नियोजन के विकल्प चुनने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें, उन पर अनचाहे गर्भधारण का बोझ न पड़े और यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि विशेष रूप से अधिक जरूरत वाले राज्यों, जिलों और ब्लॉकों में गर्भनिरोधकों की कमी को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि परिवार नियोजन कार्यक्रम का उद्देश्य अपनी पसंद और सूचित विकल्प के साथ जन्म होना चाहिए। युवाओं, किशोरों, महिलाओं और बुजुर्गों सहित सभी के लिए एक उज्ज्वल, स्वस्थ भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में सरकार के निर्णय पर प्रकाश डालते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सहयोग महत्वपूर्ण है क्योंकि हम भावी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं और परिवार नियोजन एवं प्रजनन स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार मानते हैं। उन्होंने कहा कि सही टाइमिंग और दो बच्चों के जन्म के बीच अंतराल को बढ़ावा देना, परिवार के इष्टतम आकार को प्राप्त करना और गर्भनिरोधक विकल्पों को स्वैच्छिक रूप से अपनाना स्वस्थ और खुशहाल परिवारों के पोषण के लिए महत्वपूर्ण है। इससे हमारे देश के उज्ज्वल भविष्य में योगदान मिलेगा।

राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफल योजनाओं में से एक मिशन परिवार विकास (एमपीवी) के बारे में प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि यह योजना शुरुआत में सात उच्च-केन्द्रित राज्यों के 146 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों (एचपीडी) में शुरू की गई थी। बाद में इन राज्यों के सभी जिलों और छह पूर्वोत्तर राज्यों में इसका विस्तार किया गया। नड्डा ने इस योजना के उल्लेखनीय प्रभाव पर जोर देते हुए इन राज्यों में गर्भनिरोधकों तक पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि और मातृ, शिशु तथा पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कमी होने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जिलों को इस योजना का प्राथमिक केंद्र बनाने से पूरे राज्य में टीएफआर को नीचे लाने में मदद मिली। मिशन परिवार विकास ने न केवल राज्यों के टीएफआर को कम करने में योगदान दिया है, बल्कि राष्ट्रीय टीएफआर में भी मदद की है। उन्होंने कहा कि हमें उन राज्यों में टीएफआर को कम बनाए रखने की दिशा में काम करने की जरूरत है, जिन्होंने इसे पहले ही हासिल कर लिया है। अन्य राज्यों को भी यह लक्ष्य हासिल करने की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने इन प्रयासों में लापरवाही बरतने के विरुद्ध राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आगाह किया और सभी को देश के समस्त भागों में टीएफआर को प्रतिस्थापन स्तर पर लाने की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि हमें राज्यों से प्राप्त सुझावों और एनएफएचएस आंकड़ों के आधार पर एक रणनीति बनानी चाहिए, ताकि उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके जहां टीएफआर में कोई सुधार नहीं हुआ है। नड्डा ने परिवार नियोजन और सेवा वितरण के संदेशों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में स्वास्थ्य सेवा और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं तथा विभिन्न विभागों द्वारा किए गए अथक कार्य एवं समर्पण की भी सराहना की।

अनुप्रिया पटेल ने यह भी बताया कि एमपीवी योजना को प्रारंभ में 146 जिलों में शुरू किया गया था, जिसका अब 340 से अधिक जिलों में विस्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बहुत उत्साहजनक है कि देश में आधुनिक गर्भनिरोधकों की स्वीकार्यता बढ़कर 56 प्रतिशत से अधिक हो गई है। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने कहा कि आधुनिक गर्भनिरोधकों का उपयोग 47.8 प्रतिशत (एनएफएचएस 4) से बढ़कर 56.5 प्रतिशत (एनएफएचएस-5) हो गया है। उन्होंने कहा कहा कि एनएफएचएस 5 डेटा अंतराल विधियों को अपनाने की ओर एक समग्र सकारात्मक बदलाव दर्शाता है जो मातृ एवं शिशु मृत्यु दर और रुग्णता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने में सहायक होगा। परिवार नियोजन की अधूरी रह जाने वाली जरूरतें 12.9 (एनएफएचएस प्ट) से घटकर 9.4 हो गई है जो एक उत्साहजनक उपलब्धि है।

इस अवसर पर एक नवाचार परिवार नियोजन प्रदर्शन मॉडल सुगम और हिंदी, अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में परिवार नियोजन पोस्टर का अनावरण किया गया, जिसमें विश्व जनसंख्या दिवस 2024 के लिए वर्तमान वर्ष के विषय को शामिल किया गया है। सुगम परिवार नियोजन के लिए एक विशिष्ट और नवाचार बहुउद्देशीय प्रदर्शन मॉडल है, जिसे परिवार नियोजन सेवा प्रदाताओं, आरएमएनसीएचए (प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल, किशोर स्वास्थ्य और पोषण)

परामर्शदाताओं, जमीनी स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और लाभार्थियों के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। इसे स्वास्थ्य सुविधाओं में विभिन्न स्थानों पर रणनीतिक रूप से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। सुगम का उद्देश्य सौहार्दपूर्ण वातावरण को बढ़ावा देना और परिवार नियोजन के बारे में आवश्यक जागरूकता पैदा करना है। इसमें परिवार नियोजन में पुरुषों और महिलाओं की समान भागीदारी के बारे में आवश्यक चर्चा पैदा करना, नियोजित पितृत्व को प्रोत्साहित करना, स्वस्थ टाइमिंग और दो जन्मों के बीच अंतराल पर जोर देने के साथ-साथ उपलब्ध गर्भनिरोधक विकल्पों की श्रृंखला को प्रदर्शित करना शामिल है। परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता पैदा करने और परिवार नियोजन वस्तुओं के उपयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में विकसित रेडियो स्पॉट और जिंगल्स भी लॉन्च किए गए हैं।

iTVoice® all things tech.

India's Premier IT Magazine & First Daily Tech News OTT

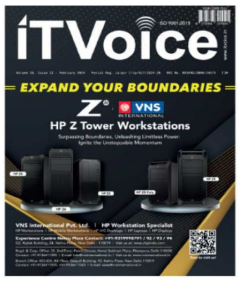

Magazines & Newspapers

Highest Digital Presence

www.itvoice.in

Daily Tech News & Podcasts

Contact for Print & Digital Marketing

+91 141 4014911
info@itvoice.in

ICPL
www.icpljpr.com

Professional IT Support

Domain & Hosting
Web Development
Customized Software Solution
Web Operation
Client / Server Management
Network Maintenance
Service Desk Support
Customized IT Support Services
Dealing in all Major Brands

Informatic Computech Private Limited

Jaipur - Rajasthan (Ph.) +91-141-2280510 md@icpljpr.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक तरूण कुमार टांक के लिये महारानी प्रिन्टर्स प्लाट नं. 17, माँ वैष्णो देवी नगर, कालवाड़ रोड, जयपुर से मुद्रित एवं 52/121, वीरतेजाजी रोड, मानसरोवर, जयपुर (राज.) से प्रकाशित। सम्पादक-तरूण कुमार टांक Email: mahanagarstambh@gmail.com